

Μέρος Ι
(Κείμενο στη χίντι γλώσσα)

अनुच्छेद XIII
हस्ताक्षर तथा लागू किया जाना

1. अवसंरचना करार का अनुसमर्थन, स्वीकरण अथवा अनुमोदन राष्ट्रों द्वारा उनकी उपयुक्त संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार संपन्न की जाएगी। यह अवसंरचना करार पंद्रहवें अनुसमर्थन, स्वीकरण अथवा अनुमोदन दस्तावेजों को जमा किए जाने के पश्चात तीसवें दिन से लागू होगा।
2. जो सदस्य इस अवसंरचना करार के लागू होने के पश्चात अनुसमर्थन, स्वीकरण अथवा अनुमोदन दस्तावेज जमा करवाते हैं, उनके लिए यह अवसंरचना करार संगत दस्तावेजों को जमा करवाए जाने की तारीख के पश्चात तीसवें दिन से लागू होगा।
3. आईएसए की स्थापना होने के बाद आईएसए की अंतरराष्ट्रीय संचालन समिति समाप्त हो जाएगी।

अनुच्छेद XIV
पाठ की डिपोजिटरी, पंजीकरण, अधिप्रमाणन

1. भारत गणराज्य की सरकार इस अवसंरचना करार की डिपोजिटरी होगी।
2. यह अवसंरचना करार संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 102 के अनुसार डिपोजिटरी द्वारा पंजीकृत होगी।
3. डिपोजिटरी इस अवसंरचना करार की सत्यापित प्रतियां सभी पक्षकारों को प्रदान करेगा।
4. इस अवसंरचना करार का हिंदी, अंग्रेजी तथा फ्रेंच पाठ एक समान प्रामाणिक होगा तथा डिपोजिटरी के अभिलेखागार में जमा किया जाएगा।

इसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी ने विधिवत प्राधिकृत होकर इस अवसंरचना करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

निकोसिया में वर्ष 2022 के दिसंबर महीने के 29 वें दिन हिंदी, अंग्रेजी तथा फ्रेंच भाषाओं में संपन्न किया गया, सभी पाठ एक समान प्रामाणिक होंगे।

हस्ताक्षर: 

हस्ताक्षरकर्ता का नाम: श्री इयोनिस कसौलाइड्स

पदनाम: विदेश मंत्री

देश: साइप्रस गणराज्य

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई एस ए) की स्थापना से संबंधित कार्य ढांचा करार

हम इस करार के पक्षकार के रूप में,

दिनांक 30 नवंबर, 2015 को आयोजित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई एस ए) से संबंधित पेरिस घोषणा और इस प्रौद्योगिकी हेतु वित्त पोषण की लागत को कम करने हेतु अपेक्षित संपुक्त प्रयास करने के लिए अपने साझी महत्वाकांक्षा का स्मरण करते हुए सौर ऊर्जा के व्यापक दोहन हेतु वर्ष 2030 तक अपेक्षित 1000 बिलियन अमरीकी डॉलर से भी अधिक के निवेश की व्यवस्था करते हुए इन जरूरतों को पूरा करने हेतु अनुकूलित भावी प्रौद्योगिकियों का मार्ग प्रशस्त करते हुए;

इस बात को स्वीकार करते हुए कि सौर ऊर्जा विभिन्न देशों को अपने देशवासियों को समृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा तथा स्थायी विकास प्रदान करने के लिए एक अपूर्व अवसर प्रदान करती है;

उन विशिष्ट एवं साझा अड़चनों को स्वीकार करते हुए जो इन देशों में सौर ऊर्जा के त्वरित एवं व्यापक प्रसार के मार्ग में अभी तक रोड़ा बनी हुई हैं;

इस बात की अभिपुष्टि करते हुए कि इन अड़चनों को दूर किया जा सकता है, यदि सौर संसाधन समृद्ध देश साथ मिलकर एक मजबूत राजनीतिक जोश एवं इरादे के साथ काम करें और यह कि अन्य बातों के साथ-साथ सभी देशों में सौर अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकियों, नवाचार अथवा क्षमता निर्माण के लिए मांगों को बेहतर ढंग से एकजुट करने से लागतों को किफायती बनाने, गुणवत्ता बढ़ाने और भरोसेमंद एवं किफायती सौर ऊर्जा लाने में मदद मिलेगी जो सब के लिए सुलभ होगी;

सभी देशों के बीच समन्वयन एवं निर्णय लेने हेतु एक कारगर तंत्र स्थापित करने की इच्छा से साथ मिलकर;

निम्नानुसार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद I उद्देश्य

पक्षकारों ने एतद्वारा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (जिसे इसके बाद आई एस ए कहा गया है), की स्थापना की है, जिसके माध्यम से वे अपनी जरूरतों के अनुसार सौर ऊर्जा को बढ़ाने संबंधी मुख्य साझा चुनौतियों को सामूहिक रूप से निपटाएंगे।

अनुच्छेद II मार्गदर्शी सिद्धांत

सदस्य देश स्वैच्छिक आधार पर शुरू किए गए कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों के माध्यम से समन्वित कार्रवाई करेंगे, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ सौर अर्थव्यवस्था, सौर प्रौद्योगिकियों, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास तथा क्षमता निर्माण के लिए मांगों को बेहतर तरीके से एकजुट करना है।

1. इस प्रयास में सदस्य देश संबंधित संगठनों, सार्वजनिक एवं निजी स्टैक होल्डरों तथा गैर-सदस्य देशों के साथ परस्पर लाभकारी संबंध स्थापित करने के लिए गहन सहयोग एवं प्रयास करेंगे।

2. प्रत्येक सदस्य देश आई एस ए के तहत एक साझा विश्लेषणात्मक सोलर अनुप्रयोग मैपिंग, अपनी जरूरतों तथा उद्देश्यों से जुड़ी संगत सूचनाओं, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए घरेलू उपायों और की गई अथवा की जाने वाली पहलों, मूल्य श्रृंखला एवं प्रचार-प्रसार प्रक्रिया के मार्ग में आने वाली अड़चनों के आधार पर सामूहिक कार्रवाई का लाभ प्राप्त करने के लिए उन सौर अनुप्रयोगों को साझा एवं अद्यतन करेंगे। सहयोग हेतु संभावनाओं का उल्लेख करने के लिए सचिवालय इन मूल्यांकनों से संबंधित आंकड़े का रख-रखाव करेगा।

3. प्रत्येक सदस्य राष्ट्र आई एस ए के लिए एक राष्ट्रीय फोकल बिंदु निर्धारित करेगा। राष्ट्रीय फोकल बिंदु में सदस्य राष्ट्रों में आई एस ए के संवाददाताओं का एक स्थायी नेटवर्क शामिल होगा। वे अन्य बातों के साथ-साथ एक-दूसरे के साथ और साथ ही संबंधित स्टैक होल्डरों के साथ बातचीत करेंगे, ताकि साझा हित वाले क्षेत्रों का पता लगया जा सके, कार्यक्रम प्रस्ताव तैयार किए जा सकें और आई एस ए के उद्देश्यों को लागू करने के संबंध में सचिवालय को सिफारिश कर सकें।

अनुच्छेद III कार्यक्रम और अन्य कार्यकलाप

1. आई एस ए के कार्यक्रमों में सचिवालय के सहयोग से अनुच्छेद I तथा II में यथावर्णित उद्देश्यों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए सदस्यों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, समन्वित रूप से शुरू की जाने वाली परियोजनाएं तथा कार्यकलाप शामिल हैं। कार्यक्रमों को इस प्रकार तैयार किया जाएगा ताकि इसका अधिक से अधिक प्रभाव हो और अधिक से अधिक संख्या में सदस्य राष्ट्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इनमें सरल, परिमापीय, संघटनमूलक लक्ष्य शामिल हैं।

2. कार्यक्रम संबंधी प्रस्तावों को सदस्यों द्वारा साझा की गई सूचनाओं के आधार पर सचिवालय के सहयोग से सभी राष्ट्रीय फोकल बिंदुओं के बीच खुले परामर्श के माध्यम से तैयार किया जाता है। किसी भी कार्यक्रम का प्रस्ताव किन्हीं दो सदस्यों अथवा सदस्य समूह अथवा सचिवालय द्वारा किया जा सकता है। सचिवालय सभी आई एस ए कार्यक्रमों के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है।

3. सचिवालय कार्यक्रम प्रस्तावों को राष्ट्रीय फोकल बिंदुओं के माध्यम से डिजिटल परिचालन द्वारा सभा को परिचालित करता है। शामिल होने के इच्छुक सदस्यों द्वारा समेकन हेतु ऐसे किसी भी कार्यक्रम प्रस्ताव को खुला समझा जाता है, यदि इसे कम-से-कम दो सदस्य राष्ट्रों का समर्थन हासिल हो और दो से अधिक राष्ट्रों द्वारा कोई आपत्ति न की गई हो।

4. शामिल होने के इच्छुक सदस्यों द्वारा एक संयुक्त घोषणा के जरिये औपचारिक तौर पर किसी कार्यक्रम प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाता है। किसी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में सभी निर्णय इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। इसका निष्पादन सचिवालय के मार्गदर्शन एवं सहयोग से प्रत्येक सदस्य राष्ट्र द्वारा अभिनिर्धारित राष्ट्र प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है।

5. वार्षिक कार्य योजना कार्यक्रमों तथा आई एस ए के अन्य कार्यकलापों का सिंहावलोकन होती है। इसे सचिवालय द्वारा सभा को प्रस्तुत किया जाता है जो यह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक कार्य योजना के सभी कार्यक्रम तथा कार्यकलाप आई एस ए के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप है।

अनुच्छेद IV सभा

1. दोनों पक्षकार एतद्वारा सभा की स्थापना करेंगे जिसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होगा जो इस कार्यक्रम को लागू करने और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु समन्वित कार्रवाई करने से संबंधित निर्णय लेंगे। इस सभा की मंत्री वर्गीय बैठक आई एस ए में वार्षिक आधार पर आयोजित की जाएगी। यह सभा विशेष परिस्थितियों में भी बैठक आयोजित कर सकता है।

2. मंत्रालय स्तर पर कार्यक्रमों का जायजा लेने और अनुच्छेद III.4 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के प्रयोजनार्थ इसे लागू करने संबंधी निर्णय लेने के लिए सभा का अल्पावधिक सत्र आयोजित किया जाता है।

3. सभा अंतराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंतर्गत कार्यक्रमों और अन्य कार्यकलापों खासकर सौर ऊर्जा के परिनियोजन, निष्पादन, विश्वसनीयता तथा लागत और वित्त के पैमाने के संबंध में सम्पूर्ण प्रभाव का आकलन करती है। इस आकलन के आधार पर सदस्य अंतराष्ट्रीय सौर गठबंधन के उद्देश्य को आगे कार्यान्वित करने के बारे में सभी आवश्यक निर्णय लेते हैं।

4. सभा महानिदेशक के चयन और परिचालन बजट के अनुमोदन सहित अंतराष्ट्रीय सौर गठबंधन के कामकाज के बारे में सभी आवश्यक निर्णय लेती है।

5. प्रत्येक सदस्य का सभा में एक वोट होता है। प्रेक्षक और भागीदार संगठन मतदान के अधिकार के बिना इसमें भाग ले सकते हैं। कार्यविधि के प्रश्नों के संबंध में निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत और मतदान के द्वारा लिये जाते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में निर्णय उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत और मतदान के द्वारा लिये जाते हैं। विशिष्ट कार्यक्रमों के बारे में निर्णय इस कार्यक्रम में भाग ले रहे सदस्यों के द्वारा लिये जाते हैं।

6. 30 नवम्बर 2015 को अंतराष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में पेरिस घोषणा के द्वारा गठित अंतराष्ट्रीय सौर गठबंधन की अंतराष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा लिये गये सभी निर्णय सभा को प्रस्तुत किये जाते हैं ताकि इन्हें उसकी प्रथम बैठक में पारित किया जा सके।

अनुच्छेद V सचिवालय

1. पक्षकार एतद्वारा इस करार के अंतर्गत अपने सामूहिक कार्य में सहायता के लिए एक सचिवालय की स्थापना करते हैं। सचिवालय में एक महानिदेशक, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, और यथापेक्षित आधार पर अन्य स्टाफ शामिल है।

2. महानिदेशक का चयन समिति द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है जिसे और एक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। महानिदेशक समिति के प्रति उत्तरदायी है।

3. महानिदेशक स्टॉफ की नियुक्ति, संगठन और सचिवालय के कामकाज तथा संसाधन जुटाने के लिए सभा के प्रति उत्तरदायी है।

4. सचिवालय सभा द्वारा कार्रवाई हेतु मामलों को तैयार करता है और सभा द्वारा सौंपे गए निर्णयों को कार्यान्वित करता है। यह सभा के निर्णयों के बाद समुचित कदम उठाये जाने और ऐसे निर्णयों के कार्यान्वयन में सदस्यों की कार्रवाइयों का समन्वय सुनिश्चित करता है। सचिवालय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य भी करेगा:

क) राष्ट्रीय फोकल बिन्दुओं को कार्यक्रम के प्रस्ताव तैयार करने में और सभा को प्रस्तुत की गई सिफारिशों में सहायता करेगा;

ख) धन जुटाने सहित प्रत्येक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सदस्यों को मार्गदर्शन और सहयोग मुहैया कराएगा;

ग) सभा की ओर से, और किसी खास कार्यक्रम में भाग ले रहे सदस्यों के समूह के द्वारा अनुरोध किये जाने पर उनकी ओर से कार्य करेगा; और खासकर सम्बद्ध भागीदारों के साथ सम्पर्क स्थापित करेगा;

घ) सभा द्वारा यथानुमोदित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के कामकाज और उसके कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित संचार, उपकरणों और क्रॉस-कटिंग के सभी साधन स्थापित करेगा और उनका प्रचालन करेगा।

अनुच्छेद VI

बजट और वित्तीय संसाधन

1. सचिवालय और सभा की प्रचालन लागतें तथा सहयोगी कामकाजों और क्रॉस-कटिंग कार्यकलापों से जुड़ी सभी लागतें अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बजट में सम्मिलित हैं। इन्हें निम्नलिखित से जुटाया जाता है:

(क) इसके सदस्यों, संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियों तथा अन्य देशों द्वारा स्वैच्छिक अंशदान;

(ख) निजी क्षेत्र से स्वैच्छिक अंशदानों द्वारा। किसी संभावित हितों के टकराव की स्थिति में सचिवालय मामले को अंशदान के स्वीकरण के अनुमोदन हेतु सभा को भेजता है;

(ग) सभा द्वारा अनुमोदित विशिष्ट कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाले राजस्व द्वारा।

2. सचिवालय समग्र निधि स्थापित करने और उसे बढ़ाने के लिए सभा के समक्ष प्रस्ताव रखेगा। समग्र निधि 16 मिलियन अमरीकी डॉलर के शुरूआती दान के साथ अंतराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बजट के लिए राजस्व उत्पन्न करेगा।

3. भारत सरकार समग्र निधि, बुनियादी ढांचे के निर्माण और आवर्ती व्यय के लिए 2016-17 से 2020-21 तक पांच वर्ष की अवधि में अंतराष्ट्रीय सौर गठबंधन को 27 मिलियन अमरीकी डॉलर का अंशदान करेगी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नामतः भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) और भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) प्रत्येक ने अंतराष्ट्रीय सौर गठबंधन समग्र निधि के निर्माण के लिए 1 मिलियन अमरीकी डॉलर का अंशदान किया है।

4. आम बजट के अंतर्गत आने वाली प्रशासनिक लागतों को छोड़कर किसी विशिष्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधनों का इस कार्यक्रम में भाग ले रहे देशों द्वारा सचिवालय के सहयोग और सहायता से आकलन किया जाता है और जुटाया जाता है।

5. अंतराष्ट्रीय सौर गठबंधन के कार्यक्रमों को छोड़कर वित्तीय और प्रशासनिक कार्यकलापों को सभा द्वारा यथानुमोदित एक अलग करार के अनुसार अन्य संगठन को आउटसोर्स किया जा सकता है।

6. सचिवालय अंतराष्ट्रीय सौर गठबंधन के लेखों की जांच के लिए सभा के अनुमोदन से किसी भी बाहरी लेखा परीक्षक को नियुक्त कर सकता है।

अनुच्छेद VII सदस्य देश की स्थिति

1. सदस्यता उन देशों के लिए खुली है जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। ऐसे देश इस करार पर हस्ताक्षर करके और अनुसमर्थन, स्वीकरण अथवा अनुमोदन का दस्तावेज प्रस्तुत करके अंतराष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य बनते हैं।

अनुच्छेद VIII भागीदार संगठन

1. सभा द्वारा संप्रभु राज्यों द्वारा गठित अंतर सरकारी क्षेत्रीय आर्थिक एकीकृत संगठनों तथा जिनमें से कम से कम एक आईएसए का सदस्य हो हित जिनमें संगठनों में आईएसए को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करने की क्षमता है उन संगठनों को सभा द्वारा भागीदार संगठन का दर्जा दिया जाए।

2. किसी विशिष्ट कार्यक्रम के संदर्भ में भागीदारों के संबंध में अंतिम निर्णय इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले राष्ट्रों द्वारा सचिवालय के अनुमोदन से लिया जाता है।

3. संयुक्त राष्ट्र अपने अंगों सहित आईएसए का रणनीतिक सहभागी होगा।

अनुच्छेद IX

पर्यवेक्षक

जिन आवेदकों का आवेदन सदस्यता के लिए लंबित है अथवा ऐसे किसी संगठन को जो आईएसए के हितों तथा लक्ष्यों को आगे ले जा सकते हैं उन्हें सभा द्वारा पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जा सकता है।

अनुच्छेद X

आईएसए का दर्जा, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां

1. आईएसए सचिवालय मेजबान राष्ट्र करार के अंतर्गत संविदा करने की क्षमता, चल-अचल संपत्तियों के अधिग्रहण और निपटान और विधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए वैधिक व्यक्तित्व रखेगा।
2. इसी मेजबान राष्ट्र करार के तहत, आईएसए सचिवालय उन विशेषाधिकारों, लागू कर रियायतों तथा उन्मुक्तियों का उपयोग करेगा जो मुख्यालयों में सभा द्वारा अनुमोदित कार्यो तथा कार्यक्रमों को स्वतंत्र रूप से निपटाने के लिए आवश्यक होगा।
3. प्रत्येक सदस्य के भूक्षेत्र के अंतर्गत, उसके राष्ट्रीय कानूनों के अधधीन और एक पृथक करार के अनुसार, यदि आवश्यक है, आईएसए सचिवालय ऐसे उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों का उपभोग कर सकेगा जैसे उसके कार्यो और कार्यक्रमों के स्वतंत्र निर्वाह के लिए आवश्यक हो।

अनुच्छेद XI

संशोधन तथा प्रत्याहरण

1. कोई भी सदस्य अवसंरचना करार के लागू होने के एक वर्ष समाप्त होने के पश्चात अवसंरचना करार में संशोधन का प्रस्ताव रख सकता है।
2. सभा द्वारा अवसंरचना करार में संशोधन को उपस्थित एवं मताधिकार का प्रयोग करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से अंगीकार किया जाएगा। जब संबंधित संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार दो-तिहाई सदस्य अपनी स्वीकृति देंगे, उसके पश्चात ही ये संशोधन प्रभावी होंगे।
3. कोई भी सदस्य डिपोजिटरी को अग्रिम तौर पर तीन महीने का नोटिस देकर मौजूदा अवसंरचना करार से प्रत्याहार कर सकता है। ऐसे प्रत्याहारण की नोटिस को डिपोजिटरी द्वारा दूसरे सदस्य को अधिसूचित की जाएगी।

अनुच्छेद XII

आईएसए की पीठ

आईएसए की पीठ भारत में होगी।

Μέρος II
(Κείμενο στην αγγλική γλώσσα)

**Framework Agreement on the establishment of the International
Solar Alliance (ISA)**

We, the Parties to this Agreement,

Recalling the Paris Declaration on the International Solar Alliance of 30th November 2015 and the shared ambition to undertake joint efforts required to reduce the cost of finance and the cost of technology, mobilize more than US \$ 1000 billion of investments needed by 2030 for massive deployment of solar energy, and pave the way for future technologies adapted to the needs,

Recognizing that solar energy provides countries with an unprecedented opportunity to bring prosperity, energy security and sustainable development to their peoples,

Acknowledging the specific and common obstacles that still stand in the way of rapid and massive scale-up of solar energy in these countries,

Affirming that these obstacles can be addressed if solar resource rich countries act in a coordinated manner, with strong political impulse and resolve, and that better harmonizing and aggregating the demand for inter alia solar finance, technologies, innovation or capacity building, across countries, will provide a strong lever to lower costs, increase quality, and bring reliable and affordable solar energy within the reach of all,

United in their desire to establish an effective mechanism of coordination and decision-making among them,

Have agreed as follows:

Article I Objective

Parties hereby establish an International Solar Alliance (hereinafter referred to as the ISA), through which they will collectively address key common challenges to the scaling up of solar energy in line with their needs.

Article II Guiding Principles

1. Members take coordinated actions through Programmes and activities launched on a voluntary basis, aimed at better harmonizing and aggregating demand for, inter alia, solar finance, solar technologies, innovation, research and development, and capacity building.
2. In this endeavor, Members cooperate closely and strive for establishing mutually beneficial relationships with relevant organizations, public and private stakeholders, and with non-member countries.
3. Each Member shares and updates, for those solar applications for which it seeks the benefits of collective action under the ISA, and based on a common analytical mapping of solar applications, relevant information regarding: its needs and objectives; domestic measures and initiatives taken or intended to be taken in order to achieve these objectives;

obstacles along the value chain and dissemination process. The Secretariat maintains a database of these assessments in order to highlight the potential for cooperation.

4. Each Member designates a National Focal Point for the ISA. National Focal Points constitute a permanent network of correspondents of the ISA in Member countries. They inter alia interact with one another and also with relevant stakeholders to identify areas of common interest, design Programmes proposals and make recommendations to the Secretariat regarding the implementation of the objectives of the ISA.

Article III Programmes and other activities

1. A Programme of the ISA consists of a set of actions, projects and activities to be taken in a coordinated manner by Members, with the assistance of the Secretariat, in furtherance of the objective and guiding principles described in article I and II. Programmes are designed in a way to ensure maximum scale effect and participation of the largest possible number of Members. They include simple, measurable, mobilizing targets.
2. Programme proposals are designed through open consultations among all National Focal Points, with the assistance of the Secretariat, and based on information shared by Members. A Programme can be proposed by any two Members or group of Members, or by the Secretariat. The Secretariat ensures coherence among all ISA Programmes.
3. Programme proposals are circulated by the Secretariat to the Assembly by digital circulation, through the network of National Focal Points. A Programme proposal is deemed open to adhesion by Members willing to join if it is supported by at least two Members and if objections are not raised by more than two countries.
4. A Programme proposal is formally endorsed by Members willing to join, through a joint declaration. All decisions regarding the implementation of the Programme are taken by Members participating in the Programme. They are carried out, with the guidance and assistance of the Secretariat, by country Representatives designated by each Member.
5. The annual work plan gives an overview of the Programmes, and other activities of the ISA. It is presented by the Secretariat to the Assembly, which ensures that all Programmes and activities of the annual work plan are within the overall objective of the ISA.

Article IV Assembly

1. The Parties hereby establish an Assembly, on which each Member is represented, to make decisions concerning the implementation of this Agreement and coordinated

actions to be taken to achieve its objective. The Assembly meets annually at the Ministerial level at the seat of the ISA. The Assembly may also meet under special circumstances.

2. Break-out sessions of the Assembly are held in order to take stock of the Programmes at Ministerial level and make decisions regarding their further implementation, in furtherance of article III.4.
3. The Assembly assesses the aggregate effect of the Programmes and other activities under the ISA, in particular in terms of deployment of solar energy, performance, reliability, as well as cost and scale of finance. Based on this assessment, Members take all necessary decisions regarding the further implementation of the objective of the ISA.
4. The Assembly makes all necessary decisions regarding the functioning of the ISA, including the selection of the Director General and approval of the operating budget.
5. Each Member has one vote in the Assembly. Observers and Partner organizations may participate without having right to vote. Decisions on questions of procedure are taken by a simple majority of the Members present and voting. Decisions on matters of substance are taken by two-third majority of the Members present and voting. Decisions regarding specific Programmes are taken by Members participating in this Programme.
6. All decisions taken by the International Steering Committee of the ISA established by the Paris Declaration on the ISA of 30th November 2015 are submitted to the Assembly for adoption at its first meeting.

Article V Secretariat

1. Parties hereby establish a Secretariat to assist them in their collective work under this Agreement. The Secretariat comprises of a Director General, who is the Chief Executive Officer, and other staff as may be required.
2. The Director General is selected by and responsible to the Assembly, for a term of four years, renewable for one further term.
3. The Director General is responsible to the Assembly for the appointment of the staff as well as the organization and functioning of the Secretariat, and also for resource mobilization.
4. The Secretariat prepares matters for Assembly action and carries out decisions entrusted to it by the Assembly. It ensures that appropriate steps are taken to follow up Assembly decisions and to co-ordinate the actions of Members in the implementation of such decisions. The Secretariat, inter alia, shall:

- a. assist the National Focal Points in preparing the Programmes proposals and recommendations submitted to the Assembly;
- b. provide guidance and support to Members in the implementation of each Programme, including for the raising of funds;
- c. act on behalf of the Assembly, or on behalf of a group of Members participating in a particular Programme, when so requested by them; and in particular establishes contacts with relevant stakeholders;
- d. set and operate all means of communication, instruments and cross-cutting activities required for the functioning of the ISA and its Programmes, as approved by the Assembly.

Article VI
Budget and Financial Resources

1. Operating costs of the Secretariat and Assembly, and all costs related to support functions and cross-cutting activities, form the budget of the ISA. They are covered by:
 - a. Voluntary contributions by its Members, UN & its agencies and other countries;
 - b. Voluntary contributions from private sector. In case of a possible conflict of interest, the Secretariat refers the matter to the Assembly for approval of the acceptance of the contribution;
 - c. Revenue to be generated from specific activities approved by the Assembly.
2. The Secretariat will make proposals before the Assembly to establish and enhance a Corpus Fund which will generate revenues for the budget of the ISA, with initial donation of US \$16 million.
3. Government of India will contribute US \$ 27 million to the ISA for creating corpus, building infrastructure and recurring expenditure over 5 year duration from 2016-17 to 2020-21. In addition, public sector undertakings of the Government of India namely Solar Energy Corporation of India (SECI) and Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) have made a contribution of US \$ 1 million each for creating the ISA corpus fund.
4. Financial resources required for the implementation of a specific Programme, other than administrative costs falling under the general budget, are assessed and mobilized by countries participating in this Programme, with the support and assistance of the Secretariat.
5. The finance and administration activities of the ISA other than Programmes may be outsourced to another organization, in accordance with a separate agreement to be approved by the Assembly.
6. The Secretariat with the approval of the Assembly may appoint an external auditor to examine the accounts of the ISA.

Article VII
Member Country status

1. Membership is open to States which are members of the United Nations. Such States become Members of the ISA by having signed this Agreement and having deposited an instrument of ratification, acceptance or approval.

Article VIII
Partner Organization

1. Partner Organization status may be granted by the Assembly to organizations that have potential to help the ISA to achieve its objectives, including regional inter-governmental economic integration organizations constituted by sovereign States and at least one of which is a member of ISA.
2. Decisions regarding partnerships to be concluded in the context of a specific Programme are taken by countries participating in this Programme, with the approval of the Secretariat.
3. United Nations including its organs will be the Strategic Partner of the ISA.

Article IX
Observers

Observer status that may be granted by the Assembly to applicants for membership whose application is pending, or to any other organization which can further the interest and objectives of the ISA.

Article X
Status, privileges and immunities of the ISA

1. The ISA Secretariat shall possess juridical personality under the Host Country Agreement, the capacity to contract, to acquire and dispose of movable and immovable properties and to institute legal proceedings.
2. Under the same Host Country Agreement, the ISA Secretariat shall enjoy such privileges, applicable tax concessions and immunities as are necessary at its Headquarters for independent discharge of its functions and programmes, approved by the Assembly.
3. Under the territory of each Member, subject to its National Laws and in accordance with a separate Agreement, if necessary; the ISA Secretariat may enjoy such immunity and privileges that are necessary for the independent discharge of its functions and programmes.

Article XI
Amendments and withdrawal

1. Any Member may propose amendments to the Framework Agreement after expiry of one year from the commencement of the Framework Agreement.
2. Amendments to the Framework Agreement shall be adopted by the Assembly by two thirds majority of the Members present and voting. The amendments shall come into force when two thirds of the Members convey acceptance in accordance with their respective constitutional processes.
3. Any member may withdraw from the present Framework Agreement, by giving a notice of three months to the Depository in advance. Notice of such withdrawal are notified to the other Members by the Depository.

Article XII
Seat of the ISA

The seat of the ISA shall be in India.

Article XIII
Signature and entry into force

1. Ratification, acceptance or approval of the Framework Agreement is effected by States in accordance with their respective constitutional processes. This Framework Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of the fifteenth instrument of ratification, acceptance or approval.
2. For Members having deposited an instrument of ratification, acceptance or approval after the entry into force of the Framework Agreement, this Framework Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of the relevant instrument.
3. Once the ISA is established, the International Steering Committee of the ISA ceases to exist.

Article XIV
Depository, registration, authentication of the text

1. The Government of the Republic of India is the Depository of the Framework Agreement.
2. This Framework Agreement is registered by the Depository pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

3. The Depositary transmits certified copies of the Framework Agreement to all Parties.
4. This Framework Agreement, of which Hindi, English and French texts are equally authentic, is deposited in the archives of the Depositary.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the Framework Agreement.

DONE at Nicosia, on this 29th day of December of year 2022, in the Hindi, English and French languages, all texts being equally authentic.

Signature:  _____

Name of Signatory: Mr. Ioannis Kasoulides

Designation: Minister of Foreign Affairs

Country: Republic of Cyprus

**Accord cadre portant création de l'Alliance solaire internationale
(ASI)**

Nous, Parties au présent Accord,

Rappelant la Déclaration de Paris du 30 novembre 2015 sur l'Alliance solaire internationale ainsi que notre ambition commune d'entreprendre les efforts conjoints nécessaires pour réduire le coût du financement et des technologies, mobiliser plus de 1000 milliards USD d'investissements requis à l'horizon 2030 pour un déploiement massif de l'énergie solaire et ouvrir la voie à des technologies futures adaptées aux besoins,

Reconnaissant que l'énergie solaire offre aux pays une possibilité sans précédent d'apporter la prospérité, la sécurité énergétique et un développement durable à leurs populations,

Conscients des obstacles spécifiques et communs qui entravent encore un déploiement rapide et massif de l'énergie solaire dans ces pays,

Affirmant que ces obstacles peuvent être surmontés si les pays riches en ressources solaires agissent de façon coordonnée, avec une impulsion et volonté politique fortes, et qu'une meilleure harmonisation et agrégation de la demande, notamment de financement, de technologies, d'innovation ou de renforcement des capacités dans le domaine de l'énergie solaire, entre les pays, constituera un puissant levier pour abaisser les prix, améliorer la qualité et mettre une énergie solaire fiable et d'un coût abordable à la portée de tous,

Unies par leur volonté commune de mettre en place un mécanisme efficace de coordination et de décision entre elles,

Sommes convenues des dispositions suivantes :

Article Ier Objectif

Les Parties créent par les présentes une Alliance solaire internationale (ci-après dénommée ASI) à travers laquelle ils apporteront une réponse collective aux principaux obstacles communs à un déploiement d'énergie solaire à l'échelle de leurs besoins.

Article II Principes directeurs

1. Les Membres prennent des mesures coordonnées par le biais de programmes et d'activités engagés sur une base volontaire, visant à mieux harmoniser et agréger la demande, notamment en matière de financement solaire, de technologies solaires, d'innovation, de recherche et de développement et de renforcement des capacités.
2. A cette fin, les Membres coopèrent étroitement et s'efforcent d'établir des relations mutuellement avantageuses avec les organisations compétentes, les parties prenantes publiques et privées et les pays non Membres.
3. Chaque membre partage et actualise, pour les applications solaires pour lesquelles il recherche les bénéfices d'une action collective dans le cadre de l'ASI, et sur la base d'une cartographie analytique commune des applications solaires, les informations pertinentes concernant : ses besoins et objectifs ; les mesures et initiatives nationales engagées ou prévues pour atteindre ces objectifs ; les obstacles rencontrés tout au long de la chaîne de

valeur et du processus de diffusion. Le Secrétariat tient une base de données de ces analyses afin de souligner le potentiel de coopération.

4. Chaque Membre désigne un Point focal national pour l'ASI. Les Points focaux nationaux constituent un réseau permanent de correspondants de l'ASI dans les pays Membres. Ils échangent notamment les uns avec les autres ainsi qu'avec les parties prenantes concernées afin de définir des domaines d'intérêt commun, et de formuler des propositions de Programmes et des recommandations à l'attention du Secrétariat en ce qui concerne la mise en œuvre des objectifs de l'ASI.

Article III **Programmes et autres activités**

1. Un Programme de l'ASI se compose d'une série d'actions, de projets et d'activités à mener de manière coordonnée par les Membres, avec l'aide du Secrétariat, conformément à l'objectif et aux principes directeurs visés aux articles Ier et II. Les Programmes sont conçus de manière à assurer un effet d'échelle optimal et la participation du plus grand nombre de Membres possible. Ils comportent des objectifs simples, quantifiables et mobilisateurs.
2. Les propositions de Programme sont élaborées à travers des consultations ouvertes entre tous les Points focaux nationaux avec l'aide du Secrétariat et sur la base des informations partagées par les Membres. Un Programme peut être proposé par deux Membres ou un groupe de Membres ou par le Secrétariat. Le Secrétariat veille à la cohérence entre tous les Programmes de l'ASI.
3. Les propositions de Programme sont communiquées par le Secrétariat à l'Assemblée par diffusion numérique, par l'intermédiaire du réseau de Points focaux nationaux. Une proposition de Programme est réputée ouverte à l'adhésion des Membres désireux de s'y associer si elle est soutenue par deux Membres au moins et si aucune objection n'est formulée par plus de deux pays.
4. Une proposition de Programme est officiellement approuvée par le biais d'une Déclaration commune par les Membres désireux de s'y associer. Toutes les décisions concernant la mise en œuvre du Programme sont prises par les Membres participant audit Programme. Elles sont exécutées sous la conduite et avec le concours du Secrétariat, par les Représentants nationaux désignés par chaque Membre.
5. Le plan de travail annuel présente une vue d'ensemble des Programmes et des autres activités de l'ASI. Il est présenté par le Secrétariat à l'Assemblée, qui veille à ce que tous les Programmes et activités dudit Plan entrent dans le cadre de l'objectif global de l'ASI.

Article IV Assemblée

1. Les Parties mettent en place par les présentes une Assemblée où chaque Membre est représenté, chargée de prendre les décisions concernant la mise en œuvre du présent Accord et les actions coordonnées à mener pour réaliser son objectif. L'Assemblée se réunit chaque année au niveau ministériel au siège de l'ASI. Elle peut également se réunir dans des circonstances spéciales.
2. Des sessions en petits groupes sont organisées entre les Membres participant à chaque programme afin de faire le bilan au niveau ministériel et de prendre les décisions concernant leur mise en œuvre ultérieure en application de l'article III.4.
3. L'Assemblée évalue l'effet cumulé des Programmes et des autres activités menées dans le cadre de l'ASI, notamment du point de vue du déploiement de l'énergie solaire, de la performance, de la fiabilité ainsi que du coût et du volume de financement. Sur la base de cette évaluation, les Membres prennent toutes les décisions nécessaires concernant la poursuite de la mise en œuvre de l'objectif de l'ASI.
4. L'Assemblée prend toutes les décisions nécessaires en ce qui concerne le fonctionnement de l'ASI, notamment le choix du Directeur général et l'approbation du budget de fonctionnement.
5. Chaque Membre dispose d'une voix à l'Assemblée. Les Observateurs et les Organisations partenaires peuvent participer sans droit de vote. Les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple des Membres présents et votants. Les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. Les décisions portant sur un programme spécifique sont prises par les Membres participant à ce programme.
6. Toutes les décisions prises par le Comité de pilotage international de l'ASI institué par la Déclaration de Paris du 30 novembre 2015 relative à l'ASI sont soumises à l'Assemblée pour adoption lors de sa première réunion.

Article V Secrétariat

1. Les Parties établissent par les présentes un Secrétariat chargé de les assister lors de leurs travaux collectifs dans le cadre du présent Accord. Le Secrétariat se compose d'un Directeur général, qui est l'administrateur général, ainsi que du personnel éventuellement nécessaire.
2. Le Directeur général est désigné par l'Assemblée et responsable devant elle pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.
3. Le Directeur général est responsable devant l'Assemblée pour la nomination du personnel et l'organisation et le fonctionnement du Secrétariat ainsi que pour la mobilisation de ressources.

4. Le Secrétariat prépare les questions pour suite à donner par l'Assemblée et exécute les décisions dont il est chargé par celle-ci. Il veille à ce que les mesures adéquates soient prises pour assurer le suivi des décisions de l'Assemblée et coordonner les actions des Membres dans la mise en œuvre de ces décisions. Le Secrétariat assure notamment les tâches ci-après :
 - a) aider les Points focaux nationaux à préparer les propositions de Programme et les recommandations soumises à l'Assemblée ;
 - b) fournir des orientations et un soutien aux Membres pour la mise en œuvre de chaque Programme, notamment pour la collecte de fonds ;
 - c) agir au nom de l'Assemblée, ou au nom d'un groupe de Membres participant à un Programme spécifique, à leur demande, et notamment nouer des contacts avec les parties prenantes concernées ;
 - d) établir et mettre en œuvre tous moyens de communications, instruments et activités transversales requis pour le fonctionnement de l'ASI et ses programmes, tels qu'approuvés par l'Assemblée.

Article VI

Budget et ressources financières

1. Les frais de fonctionnement du Secrétariat et de l'Assemblée, ainsi que tous les frais liés aux fonctions d'appui et aux activités transversales constituent le budget de l'ASI. Ils sont couverts par :
 - a) des contributions volontaires de ses Membres, des Nations Unies et de leurs institutions ainsi que d'autres pays ;
 - b) des contributions volontaires du secteur privé. En cas de conflit d'intérêt éventuel, le Secrétariat soumet la question à l'Assemblée pour approbation de l'acceptation de la contribution ;
 - c) les recettes pouvant être générées par des activités spécifiques approuvées par l'Assemblée.
2. Le Secrétariat présente des propositions à l'Assemblée en vue de mettre en place et de développer un Fonds de dotation qui générera des recettes pour le budget de l'ASI, avec une dotation initiale de 16 millions USD.
3. Le Gouvernement de l'Inde contribuera à hauteur de 27 millions USD à l'ASI pour la création du fonds, la mise en place des infrastructures ainsi que les dépenses récurrentes sur une période de cinq ans, de 2016-17 à 2020-21. Par ailleurs, les entreprises du secteur public du gouvernement indien, à savoir Solar Energy Corporation of India (SECI) et Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) ont apporté une contribution d'un million USD chacune pour la création du fonds de dotation de l'ASI.
4. Les ressources financières nécessaires pour la mise en œuvre d'un Programme spécifique, autres que les frais administratifs relevant du budget général, sont évaluées et mobilisées par les pays participant à ce Programme avec l'aide et le soutien du Secrétariat.
5. Les activités financières et administratives de l'ASI autres que les Programmes peuvent être sous-traitées à une autre organisation, conformément à un accord séparé à approuver par l'Assemblée.

6. Avec l'accord de l'Assemblée, le Secrétariat peut désigner un auditeur externe pour examiner les comptes de l'ASI.

Article VII Statut de pays membre

1. L'adhésion est ouverte aux États membres des Nations Unies. Ces États deviennent Membres de l'ASI après avoir signé le présent Accord et déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article VIII Organisation partenaire

1. Le statut d'Organisation partenaire peut être accordé par l'Assemblée à des organisations susceptibles d'aider l'ASI à réaliser ses objectifs, notamment des organisations intergouvernementales d'intégration économique régionale constituées par des États souverains dont l'un au moins est Membre de l'ASI.
2. Les décisions relatives aux partenariats à conclure dans le cadre d'un Programme spécifique sont prises par les pays participant à ce Programme avec l'approbation du Secrétariat.
3. Les Nations Unies, y compris leurs organes, seront le Partenaire stratégique de l'ASI.

Article IX Observateurs

Le statut d'Observateur peut être accordé par l'Assemblée à des candidats à l'adhésion dont la demande est pendante ou à toute autre organisation pouvant servir les intérêts et objectifs de l'ASI.

Article X Statut, privilèges et immunités de l'ASI

1. Le Secrétariat de l'ASI possède la personnalité juridique en vertu de l'Accord de siège ainsi que la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens meubles et immeubles et d'ester en justice.
2. En vertu dudit Accord de siège, le Secrétariat de l'ASI jouit des privilèges, avantages fiscaux et immunités applicables nécessaires à son Siège pour s'acquitter de ses fonctions et exécuter ses programmes en toute indépendance, et approuvés par l'Assemblée.
3. Sur le territoire de chaque Membre, sous réserve de sa législation nationale et conformément à un Accord séparé, si nécessaire, le Secrétariat de l'ASI peut jouir des immunités et privilèges nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions et exécuter ses programmes en toute indépendance.

Article XI
Amendements et retrait

1. Tout Membre peut proposer des amendements à l'Accord cadre après l'expiration d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord cadre.
2. Les amendements à l'Accord cadre sont adoptés par l'Assemblée à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. Ces amendements entrent en vigueur lorsque les deux tiers des Membres ont exprimé leur approbation conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
3. Tout Membre peut se retirer du présent Accord cadre moyennant un préavis de trois mois adressé au Dépositaire. Ce retrait est notifié aux autres Membres par le Dépositaire.

Article XII
Siège de l'ASI

Le siège de l'ASI est établi en Inde.

Article XIII
Signature et entrée en vigueur

1. L'Accord cadre est ratifié, accepté ou approuvé par les États conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Il entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt du quinzième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Pour les Membres qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après l'entrée en vigueur de l'Accord cadre, celui-ci entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de l'instrument en question.
3. Une fois l'ASI établie, le Comité directeur international de l'ASI cesse d'exister.

Article XIV
Dépositaire, enregistrement, authentification du texte

1. Le Gouvernement de la République de l'Inde est dépositaire de l'Accord cadre.
2. Le présent Accord cadre est enregistré par le Dépositaire conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
3. Le Dépositaire transmet des copies certifiées conformes de l'Accord cadre à toutes les Parties.

4. Le présent Accord cadre, dont les textes français, hindi, et anglais font également foi, est déposé aux archives du Dépositaire.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé l'Accord cadre.

FAIT à Nicosie, le 29 décembre 2022, en langues française, hindi, et anglaise, tous les textes faisant également foi.

Signature:  _____

Nom du signataire: Ioannis Kasoulides

La désignation: Ministre des Affaires Étrangères

Pays: République de Chypre

Μέρος IV
(Κείμενο στην ελληνική γλώσσα)

**Συμφωνία Πλαίσιο για την Ίδρυση της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας
(ΔΗΣ)**

Εμείς, τα Μέρη της παρούσας Συμφωνίας,

Υπενθυμίζοντας τη Διακήρυξη του Παρισιού για τη Διεθνή Ηλιακή Συμμαχία της 30^{ης} Νοεμβρίου 2015 και την κοινή φιλοδοξία να αναλάβουμε κοινές προσπάθειες οι οποίες απαιτούνται για τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης και του κόστους τεχνολογίας, με την ανάπτυξη επενδύσεων άνω των 1000 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που απαιτούνται έως το 2030 για τη μαζική ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας και για την προετοιμασία του εδάφους για μελλοντικές τεχνολογίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες,

Αναγνωρίζοντας ότι η ηλιακή ενέργεια παρέχει στα κράτη μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία να επιφέρουν ευημερία, ενεργειακή ασφάλεια και βιώσιμη ανάπτυξη στους λαούς τους,

Παραδεχόμενοι τα συγκεκριμένα και κοινά εμπόδια που εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την ταχεία και μαζική ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας στις χώρες αυτές,

Επιβεβαιώνοντας ότι τα εμπόδια αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν εάν οι πλούσιες σε ηλιακή ενέργεια χώρες ενεργήσουν κατά συντονισμένο τρόπο, με ισχυρή πολιτική ώθηση και αποφασιστικότητα και ότι η καλύτερη εναρμόνιση και συγκέντρωση της ζήτησης, μεταξύ άλλων, για ηλιακή χρηματοδότηση, τεχνολογίες, καινοτομία ή ανάπτυξη ικανοτήτων, σε όλες τις χώρες, θα παρέχει έναν ισχυρό μοχλό για μείωση του κόστους, αύξηση της ποιότητας και θα παρέχει αξιόπιστη και οικονομική ηλιακή ενέργεια προσιτή σε όλους.

Ενωμένοι στην επιθυμία τους να ιδρύσουν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό συντονισμού και λήψης αποφάσεων μεταξύ τους,

Συμφωνήσαμε τα ακόλουθα:

Άρθρο I Σκοπός

Με την παρούσα, τα Μέρη ιδρύουν μια Διεθνή Ηλιακή Συμμαχία (εφεξής αναφερόμενη ως «ΔΗΣ»), μέσω της οποίας θα αντιμετωπίζουν συλλογικά βασικές κοινές προκλήσεις για την αύξηση της χρήσης της ηλιακής ενέργειας σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Άρθρο II Κατευθυντήριες Αρχές

1. Τα Μέλη αναλαμβάνουν συντονισμένες δράσεις μέσω Προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που εκκινούν σε εθελοντική βάση, με στόχο την καλύτερη εναρμόνιση και συγκέντρωση της ζήτησης, μεταξύ άλλων, για ηλιακή χρηματοδότηση, ηλιακές τεχνολογίες, καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη, και ανάπτυξη ικανοτήτων.
2. Στην προσπάθεια αυτή, τα Μέλη συνεργάζονται στενά και επιδιώκουν τη δημιουργία αμοιβαία επωφελών σχέσεων με αντίστοιχους οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και με χώρες που δεν είναι μέλη.
3. Κάθε Μέλος κοινοποιεί και ενημερώνει, για εκείνες τις ηλιακές εφαρμογές για τις οποίες επιδιώκει τα οφέλη συλλογικής δράσης στο πλαίσιο της ΔΗΣ, και με βάση μια κοινή αναλυτική χαρτογράφηση των ηλιακών εφαρμογών, σχετικές πληροφορίες αναφορικά με:

τις ανάγκες και τους στόχους του· τα εγχώρια μέτρα και πρωτοβουλίες που λαμβάνονται ή πρόκειται να ληφθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών· τα εμπόδια στην αλυσίδα αξίας και στη διαδικασία διάδοσης. Η Γραμματεία διατηρεί βάση δεδομένων αυτών των αξιολογήσεων, προκειμένου να επισημάνει τη δυνατότητα συνεργασίας.

4. Κάθε Μέλος ορίζει ένα Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη ΔΗΣ. Τα Εθνικά Σημεία Αναφοράς αποτελούν ένα μόνιμο δίκτυο ανταποκριτών της ΔΗΣ στις χώρες Μέλη. Μεταξύ άλλων, αλληλεπιδρούν το ένα με το άλλο, καθώς και με τους σχετικούς φορείς για τον προσδιορισμό τομέων κοινού ενδιαφέροντος, τον σχεδιασμό προτάσεων Προγραμμάτων και την υποβολή συστάσεων προς τη Γραμματεία αναφορικά με την υλοποίηση των στόχων της ΔΗΣ.

Άρθρο III **Προγράμματα και άλλες δραστηριότητες**

1. Ένα Πρόγραμμα της ΔΗΣ αποτελείται από ένα σύνολο δράσεων, έργων και δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναληφθούν κατά συντονισμένο τρόπο από τα Μέλη, με τη συνδρομή της Γραμματείας, για την προαγωγή του σκοπού και των κατευθυντήριων αρχών που περιγράφονται στο άρθρο I και II. Τα Προγράμματα σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζουν τη μέγιστη επίδραση και συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού Μελών. Περιλαμβάνουν απλούς, μετρήσιμους, κινητήριους στόχους.
2. Οι προτάσεις Προγραμμάτων σχεδιάζονται μέσω ανοικτών διαβουλεύσεων μεταξύ όλων των Εθνικών Σημείων Αναφοράς, με τη συνδρομή της Γραμματείας και βάσει πληροφοριών που μοιράζονται από τα Μέλη. Ένα Πρόγραμμα μπορεί να προταθεί από οποιαδήποτε δύο Μέλη ή ομάδα Μελών, ή από τη Γραμματεία. Η Γραμματεία διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ όλων των Προγραμμάτων της ΔΗΣ.
3. Οι προτάσεις Προγραμμάτων διανέμονται από τη Γραμματεία προς τη Συνέλευση με ψηφιακή διανομή, μέσω του δικτύου των Εθνικών Σημείων Αναφοράς. Μια πρόταση Προγράμματος θεωρείται ανοικτή για προσχώρηση από τα Μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν, εάν υποστηρίζεται από τουλάχιστον δύο Μέλη και εάν δεν εγερθούν αντιρρήσεις από περισσότερες από δύο χώρες.
4. Μια πρόταση Προγράμματος εγκρίνεται επίσημα από τα Μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν, μέσω μιας κοινής δήλωσης. Όλες οι αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος λαμβάνονται από τα Μέλη που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Αυτές εκτελούνται, με την καθοδήγηση και τη συνδρομή της Γραμματείας, από Εκπροσώπους χωρών που ορίζονται από κάθε Μέλος.
5. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών παρέχει μια επισκόπηση των Προγραμμάτων, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων της ΔΗΣ. Αυτό παρουσιάζεται από τη Γραμματεία προς τη Συνέλευση, η οποία διασφαλίζει ότι όλα τα Προγράμματα και δραστηριότητες του ετήσιου σχεδίου δράσης εμπίπτουν εντός του γενικού σκοπού της ΔΗΣ.

Άρθρο IV Συνέλευση

1. Τα Μέρη με το παρόν ιδρύουν μια Συνέλευση, στην οποία εκπροσωπείται κάθε Μέλος, για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και τις συντονισμένες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την επίτευξη του σκοπού της. Η Συνέλευση συνέρχεται ετησίως σε Υπουργικό επίπεδο στην έδρα της ΔΗΣ. Η Συνέλευση μπορεί επίσης να συνέρχεται υπό ειδικές περιστάσεις.
2. Διεξάγονται ενδιάμεσες συνεδριάσεις της Συνέλευσης προκειμένου να γίνει απολογισμός των Προγραμμάτων σε Υπουργικό επίπεδο και να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την περαιτέρω εφαρμογή τους, κατ' εφαρμογή του άρθρου III.4.
3. Η Συνέλευση αξιολογεί τη συνολική επίδραση των Προγραμμάτων και των άλλων δραστηριοτήτων υπό τη ΔΗΣ, ιδίως όσον αφορά στην ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας, την απόδοση, την αξιοπιστία, καθώς και το κόστος και την κλίμακα χρηματοδότησης. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, τα Μέλη λαμβάνουν όλες τις αναγκαίες αποφάσεις σχετικά με την περαιτέρω υλοποίηση του σκοπού της ΔΗΣ.
4. Η Συνέλευση λαμβάνει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις αναφορικά με τη λειτουργία της ΔΗΣ, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του Γενικού Διευθυντή και της έγκρισης του προϋπολογισμού λειτουργίας.
5. Κάθε Μέλος έχει μία ψήφο στη Συνέλευση. Παρατηρητές και Οργανισμοί Εταίροι μπορούν να συμμετέχουν χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου. Αποφάσεις επί ερωτήσεων διαδικασίας λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των Μελών που είναι παρόντα και ψηφίζουν. Αποφάσεις επί θεμάτων ουσίας λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων των Μελών που είναι παρόντα και ψηφίζουν. Αποφάσεις σχετικά με συγκεκριμένα Προγράμματα λαμβάνονται από τα Μέλη που συμμετέχουν στα Προγράμματα αυτά.
6. Όλες οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τη Διεθνή Συντονιστική Επιτροπή της ΔΗΣ η οποία ιδρύθηκε από τη Διακήρυξη του Παρισιού για την ΔΗΣ της 30^{ης} Νοεμβρίου 2015 υποβάλλονται στη Συνέλευση για υιοθέτηση κατά την πρώτη της συνεδρίαση.

Άρθρο V Γραμματεία

1. Τα Μέρη ιδρύουν μια Γραμματεία για να τους συνδράμει στη συλλογική τους εργασία στη βάση της παρούσας Συμφωνίας. Η Γραμματεία αποτελείται από έναν Γενικό Διευθυντή, ο οποίος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος, και άλλο προσωπικό που μπορεί να απαιτηθεί.
2. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται από και είναι υπόλογος προς τη Συνέλευση, για μια θητεία τεσσάρων ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για ακόμα μια φορά.
3. Ο Γενικός Διευθυντής είναι υπόλογος προς τη Συνέλευση για τον διορισμό του προσωπικού καθώς και για την οργάνωση και τη λειτουργία της Γραμματείας, και επίσης για την κινητοποίηση των πόρων.

4. Η Γραμματεία προετοιμάζει θέματα για δράσεις από τη Συνέλευση και εκτελεί τις αποφάσεις που της ανατίθενται από τη Συνέλευση. Διασφαλίζει τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την παρακολούθηση των αποφάσεων της Συνέλευσης και τον συντονισμό των δράσεων των Μελών κατά την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών. Η Γραμματεία, μεταξύ άλλων:
- α) βοηθά τα Εθνικά Σημεία Αναφοράς στην προετοιμασία των προτάσεων Προγραμμάτων και συστάσεων που υποβάλλονται στη Συνέλευση·
 - β) παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη στα Μέλη κατά την υλοποίηση κάθε Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης και της συγκέντρωσης κεφαλαίων·
 - γ) ενεργεί εκ μέρους της Συνέλευσης, ή εκ μέρους μιας ομάδας Μελών που συμμετέχουν σε ένα συγκεκριμένο Πρόγραμμα, όταν αυτό ζητηθεί από αυτά· και ειδικότερα δημιουργεί επαφές με σχετικούς φορείς·
 - δ) καθορίζει και λειτουργεί όλα τα μέσα επικοινωνίας, εργαλεία και οριζόντιες δραστηριότητες που απαιτούνται για τη λειτουργία της ΔΗΣ και των Προγραμμάτων της, όπως εγκρίνονται από τη Συνέλευση.

Άρθρο VI **Προϋπολογισμός και Οικονομικοί Πόροι**

Τα λειτουργικά έξοδα της Γραμματείας και της Συνέλευσης, καθώς και όλα τα έξοδα που σχετίζονται με υποστηρικτικές λειτουργίες και οριζόντιες δραστηριότητες, αποτελούν τον προϋπολογισμό της ΔΗΣ. Καλύπτονται από:

- α) Εθελοντικές εισφορές από τα Μέλη της, τον ΟΗΕ και τις οργανώσεις του και άλλες χώρες·
- β) Εθελοντικές εισφορές από τον ιδιωτικό τομέα. Σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, η Γραμματεία παραπέμπει το θέμα στη Συνέλευση για έγκριση της αποδοχής της εισφοράς·
- γ) Έσοδα που θα προκύψουν από συγκεκριμένες δραστηριότητες που εγκρίνονται από τη Συνέλευση.

Η Γραμματεία θα υποβάλει προτάσεις ενώπιον της Συνέλευσης για την ίδρυση και ενίσχυση ενός Αρχικού Κεφαλαίου, που θα δημιουργεί έσοδα για τον προϋπολογισμό της ΔΗΣ, με αρχική δωρεά 16 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Η Κυβέρνηση της Ινδίας θα συνεισφέρει 27 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στη ΔΗΣ για τη δημιουργία του κεφαλαίου, την κατασκευή υποδομών και τις επαναλαμβανόμενες δαπάνες κατά τη διάρκεια 5 ετών, από το 2016-17 έως το 2020-21. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα της Κυβέρνησης της Ινδίας, ήτοι η Solar Energy Corporation of India (SECI) και η Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA), έχουν συνεισφέρει ένα εκατομμύριο δολάρια η κάθε μία για τη δημιουργία του αρχικού κεφαλαίου της ΔΗΣ.

Οι οικονομικοί πόροι που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου Προγράμματος, εκτός από τα διοικητικά έξοδα που εμπίπτουν στον γενικό προϋπολογισμό, αξιολογούνται και κινητοποιούνται από τις χώρες που συμμετέχουν στο εν λόγω Πρόγραμμα, με την υποστήριξη και τη συνδρομή της Γραμματείας.

Οι οικονομικές και διοικητικές δραστηριότητες της ΔΗΣ εκτός των Προγραμμάτων μπορούν να ανατεθούν σε άλλον οργανισμό, σύμφωνα με ξεχωριστή συμφωνία που θα εγκριθεί από τη Συνέλευση.

Η Γραμματεία με την έγκριση της Συνέλευσης μπορεί να διορίσει εξωτερικό ελεγκτή για να εξετάσει τους λογαριασμούς της ΔΗΣ.

Άρθρο VII Καθεστώς Χώρας Μέλους

Το καθεστώς μέλους είναι ανοικτό για Κράτη που είναι μέλη των Ηνωμένων Εθνών. Τα Κράτη αυτά γίνονται Μέλη της ΔΗΣ έχοντας υπογράψει την παρούσα Συμφωνία και έχοντας καταθέσει έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης.

Άρθρο VIII Οργανισμός-Εταίρος

1. Το καθεστώς Οργανισμού-Εταίρου μπορεί να χορηγηθεί από τη Συνέλευση σε οργανισμούς που έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν την ΔΗΣ να επιτύχει τους σκοπούς της, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών διακυβερνητικών οργανισμών οικονομικής ολοκλήρωσης που αποτελούνται από κυρίαρχα Κράτη και τουλάχιστον ένα από τα οποία είναι μέλος της ΔΗΣ.
2. Οι αποφάσεις σχετικά με τις συνεργασίες που πρόκειται να συναφθούν στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου Προγράμματος λαμβάνονται από τις χώρες που συμμετέχουν στο εν λόγω Πρόγραμμα, με την έγκριση της Γραμματείας.
3. Τα Ηνωμένα Έθνη, συμπεριλαμβανομένων των οργάνων τους, θα είναι ο Στρατηγικός Εταίρος της ΔΗΣ.

Άρθρο IX Παρατηρητές

Καθεστώς Παρατηρητή μπορεί να χορηγηθεί από τη Συνέλευση σε όσους υποβάλλουν αίτηση για να γίνουν μέλη και των οποίων η αίτηση εκκρεμεί, ή σε οποιοδήποτε άλλο οργανισμό που μπορεί να προάγει τα συμφέροντα και τους στόχους της ΔΗΣ.

Άρθρο X Καθεστώς, προνόμια και ασυλίες της ΔΗΣ

1. Η Γραμματεία της ΔΗΣ διαθέτει νομική προσωπικότητα βάσει της Συμφωνίας Χώρας Υποδοχής, την ικανότητα να συνάπτει συμβάσεις, να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να κινεί νομικές διαδικασίες.
2. Βάσει της ίδιας Συμφωνίας Χώρας Υποδοχής, η Γραμματεία της ΔΗΣ απολαμβάνει τέτοια προνόμια, τις ισχύουσες φορολογικές απαλλαγές και ασυλίες που απαιτούνται στα Κεντρικά Γραφεία της για την ανεξάρτητη εκτέλεση των λειτουργιών και των προγραμμάτων της, τα οποία εγκρίνονται από τη Συνέλευση.
3. Στην επικράτεια κάθε Μέλους, με την επιφύλαξη της Εθνικής Νομοθεσίας του και σύμφωνα με ξεχωριστή Συμφωνία, εάν είναι απαραίτητο· η Γραμματεία της ΔΗΣ μπορεί να απολαμβάνει τέτοιας ασυλίας και προνομίων που είναι απαραίτητα για την ανεξάρτητη εκτέλεση των λειτουργιών και των προγραμμάτων της.

Άρθρο XI

Τροποποιήσεις και αποχώρηση

1. Οποιοδήποτε Μέλος μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις στη Συμφωνία-Πλαίσιο μετά την παρέλευση ενός έτους από την έναρξη της Συμφωνίας-Πλαίσιο.
2. Τροποποιήσεις της Συμφωνίας-Πλαίσιο υιοθετούνται από τη Συνέλευση με πλειοψηφία δύο τρίτων των Μελών που είναι παρόντα και ψηφίζουν. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ όταν τα δύο τρίτα των Μελών γνωστοποιήσουν αποδοχή σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές τους διαδικασίες.
3. Οποιοδήποτε Μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο, δίδοντας πρότερη ειδοποίηση τριών μηνών προς τον Θεματοφύλακα. Η ειδοποίηση της εν λόγω αποχώρησης κοινοποιείται στα άλλα Μέλη από τον Θεματοφύλακα.

Άρθρο XII

Έδρα της ΔΗΣ

Η έδρα της ΔΗΣ είναι στην Ινδία.

Άρθρο XIII

Υπογραφή και έναρξη ισχύος

1. Η επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση της Συμφωνίας- Πλαίσιο πραγματοποιείται από Κράτη σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές διαδικασίες τους. Η παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης του δέκατου πέμπτου εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης.
2. Για Μέλη που έχουν καταθέσει έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας-Πλαίσιο, η παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού εγγράφου.
3. Με την ίδρυση της ΔΗΣ, η Διεθνής Συντονιστική Επιτροπή της ΔΗΣ παύει να υφίσταται.

Άρθρο XIV

Θεματοφύλακας, πρωτοκόλληση, αυθεντικότητα του κειμένου

1. Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας είναι ο Θεματοφύλακας της Συμφωνίας-Πλαίσιο.
2. Η παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο πρωτοκολλείται από τον Θεματοφύλακα σύμφωνα με το Άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
3. Ο Θεματοφύλακας διαβιβάζει επικυρωμένα αντίγραφα της Συμφωνίας-Πλαίσιο σε όλα τα Μέρη.

4. Η παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο, της οποίας τα κείμενα στα Χίντι, Αγγλικά και Γαλλικά, είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στα αρχεία του Θεματοφύλακα.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι κάτωθι υπογράφωντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, έχουν υπογράψει τη Συμφωνία-Πλαίσιο.

ΕΓΙΝΕ στη, την ημέρα του έτους, στις γλώσσες Χίντι, Αγγλικά και Γαλλικά, όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Υπογραφή: _____

Όνομα του υπογράφοντος: _____

Θέση: _____

Χώρα: _____